

विचार बिन्दु

जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते। उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। –श्रीमद्भगवद्गीता

नियम के सामने मनुष्य

‘तु लसी बब्बा कह गए हैं–तुलसी और सनातन के आलोक में समकालीन जीवन तथा मानवीय मूल्यों पर साप्ताहिक अतिथि विचार–शृंखला की यह चौथी कड़ी है जो न्याय पर केन्द्रित है। ऑकरेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हम आँकार पर्वत की परिक्रमा पर निकले थे। नीचे नर्मदा का हरा जल था, ऊपर ढलान पर पत्थरों के बीच नए रोपे पौधों की कतारें। हर पौधे के चारों ओर माटी की गोल मेंड बनी थी, थाला, जिसमें डाला पानी जड़ों के पास ठहर सके। कुछ युवक–युवतियाँ नीचे के कुंड से बाल्टियाँ भरकर ऊपर ला रहे थे।

एक पेड़ के तने से गते का टुकड़ा बाँधा था। उस पर नाम लिखे थे और हर नाम के आगे एक ही संख्या: दस बाल्टी। नियम साफ था, सबके लिए बराबर। किसी के साथ पक्षपात नहीं।

पुष्पा ने गता पड़ा, फिर ढलान देखी। सबखों दस–दस बाल्टी। पै कोऊ नैचें के पौधन खों पानी दै रओ, कोऊ ऊपर की चढ़ाई पै हीफ़ रओ। जा बराबरी आय कि निरी गिनती?

मैं कुछ कहता, उससे पहले बाल्टी रखती एक युवती ने अपनी हथेली दिखाई। हल्थे की धँसक से लाल लकीर पड़ गई थी। वह ऊपर की कतार पर थी। बोली कुछ नहीं, बस हथेली पोंछी और फिर नीचे उतर गई।

यही इस कड़ी का प्रश्न है: नियमसम्मत निर्णय अन्यायपूर्ण परिणाम दे, तब सुधार कहाँ हो? नियम हमें भरोसा देता है कि व्यवहार पहचान देखकर नहीं बदलेगा। उसका यह गुण बहुमूल्य है। पर जिन पर वह लागू होता है, उनकी परिस्थितियाँ बराबर नहीं होती। बराबर गिनती के भीतर असमान श्रम छिप सकता है।

राम भरत की चित्रकूट में राजधर्म समझाते हैं:–

मुखिआ मुखु सो चाहिए खान पान कहूँ एक।

पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक॥

रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, दोहा 3 15।

मुख अकेला खाता है, पर पोषण हर अंग तक विवेक से पहुँचाता है। दोहे का भार ‘सहित बिबेक’ पर है। मुख हाथ और पाँव को बराबर कौर नहीं देता; जिस अंग को जितनी जरूरत है, उतना पहुँचाता है। मुखिया का न्याय गिनती की समानता नहीं, आवश्यकता की पहचान है।

पुष्पा ने तुरंत टोका, पै विवेक कौन को? मुखिया अपनेई विवेक खों आखिरी बात मान बैठे, तौ? प्रश्न ठीक जगह लगा था। मुखिया का विवेक भी जाँच माँगता है। इसी चित्रकूट की सभा में वसिष्ठ पहले स्वीकार करते हैं कि भरत के प्रति उनका अनुराग है, फिर राम से कहते हैं:

भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचारु बहोरि।

करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि॥

रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, दोहा 258।

पहले आदर से सुनना, फिर विचार। निर्णय में सज्जनों की सम्मति, लोकमत, राजनीति और वेद, चारों का निचोड़ आए। वसिष्ठ का अपना झुकाव स्वीकार कर लेना इस दोहे से पहले की सबसे बड़ी बात है। जो निर्णय करता है, वह अपने झुकाव को पहले पहचान ले, तभी सुनवाई निष्पक्ष होती है। और सुनवाई का अर्थ हर माँग मान लेना नहीं; भरत की प्रार्थना सुनी गई, पर राम वन में ही रहे। सुनने वाले की जवाबदेही बची, मर्यादा भी।

मैंने अपनी आसक्ति रखी, पर छूट देने लगें तो हर कोई अपनी कठिनाई बताएगा। अपने आदमी को छूट, दूसरे को नियम, यही तो पक्षपात है।

जेई तौ हम पूछ रह है, पुष्पा बोलीं। छूट की सोई मेड़ चाउने, नई तौ थाले के पानी चाई सबरी

बह जैहै।

ब्रह्मसूत्र में भोजन के नियम पर एक सूत्र है:–

सर्वाङ्गानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्॥

ब्रह्मसूत्र 3.4.28।

प्राणसंकट में सब प्रकार के अन्न की अनुमति है, क्योंकि श्रुति में ऐसा दिखता है। शांकरभाष्य उपस्थित का प्रसंग खोलता है: अकाल में जूटे उड़द लेना जीवन बचाने के लिए अनिवार्य था, पर उसी के साथ

बह जैहै।

ब्रह्मसूत्र में भोजन के नियम पर एक सूत्र है:–

सर्वाङ्गानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्॥

ब्रह्मसूत्र 3.4.28।

प्राणसंकट में सब प्रकार के अन्न की अनुमति है, क्योंकि श्रुति में ऐसा दिखता है। शांकरभाष्य उपस्थित का प्रसंग खोलता है: अकाल में जूटे उड़द लेना जीवन बचाने के लिए अनिवार्य था, पर उसी के साथ बह जैहै।

ब्रह्मसूत्र में भोजन के नियम पर एक सूत्र है:–

सर्वाङ्गानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्॥

ब्रह्मसूत्र 3.4.28।

प्राणसंकट में सब प्रकार के अन्न की अनुमति है, क्योंकि श्रुति में ऐसा दिखता है। शांकरभाष्य उपस्थित का प्रसंग खोलता है: अकाल में जूटे उड़द लेना जीवन बचाने के लिए अनिवार्य था, पर उसी के साथ

बह जैहै।

ब्रह्मसूत्र में भोजन के नियम पर एक सूत्र है:–

सर्वाङ्गानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्॥

ब्रह्मसूत्र 3.4.28।

प्राणसंकट में सब प्रकार के अन्न की अनुमति है, क्योंकि श्रुति में ऐसा दिखता है। शांकरभाष्य उपस्थित का प्रसंग खोलता है: अकाल में जूटे उड़द लेना जीवन बचाने के लिए अनिवार्य था, पर उसी के साथ बह जैहै।

ब्रह्मसूत्र में भोजन के नियम पर एक सूत्र है:–

ब्रह्मसूत्र में भोजन के नियम पर एक सूत्र है:–

–अतिथि सम्पादक,

डॉ. दीप नारायण पाण्डेय

(इंडियन फारेस्ट सर्विस से सेवानिवृत्त, वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान सहित अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर)

(यह लेखक के निजी विचार हैं और ‘सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत’ से प्रेरित हैं।)

संपादकीय

गांव का बेटा, गांव का भाई बदल रहा है

52600 गांवों की किस्मत

सीएम भजनलाल शर्मा ने 3 साल में ग्रामीण समृद्धि का नया अध्याय लिखा, पं. दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय को खेत, चौपाल और कारखानों में साकार किया



पूर्णिमा जैमिनी

भारत की आर्थिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की गाथा को गढ़ने में गाँवों और किसानों की भूमिका सदैव अग्रणी रही है। हरित क्रांति से लेकर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता तक, गाँवों और किसानों ने अपने खून पसीने से सींच कर जिस भारत के स्वाभिमान की रक्षा की, आज वे गाँव और किसान ही इस नए भारत का स्वाभिमान हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था को अपने कठोर परिश्रम और मजबूत कंधों पर संभालने वाले किसानों ने कभी नहीं सोचा होगा कि खेत की मिट्टी में सने, दूध बेचने वाला कभी नेतृत्व भी कर सकेगा। उन्होंने देश की नींव के पथ्थर बनने का संकल्प किया था लेकिन धीरे री धरती ने उन्हें अपने माथे का तिलक बनाया। ऐसे ही भारत के छोटे–से गांव अटारी से निकलकर आपणे अग्रणी राजस्थान के उदघोष से देश–विदेश को गुंजायमान करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भी प्रदेश के गाँवों में ही सुकुन की नींद पाते हैं। स्वयं को गाँव का बेटा कहने वाले भजनलाल शर्मा गाँव की मिट्टी, गाँव का अपनापन और गाँवों में बसती भारत की रीढ़ को मजबूत करने के लिए सीधे उनके द्वार पर पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री

भजनलाल शर्मा का मानना है कि अपनों

का विश्वास और स्नेह ही वह शक्ति है जो जनसेवा के संकल्पों को जन्म देती है। इस आत्मीय जुड़ाव की सहज अभिव्यक्ति जालौर जिले की पंसेरी ग्राम पंचायत में देखने को मिली, जहाँ ग्राम विकास चौपाल के बाद मुख्यमंत्री ने भेमाराम के निवास पर ग्रामीणों के साथ रात्रि भोजन किया। भजनलाल शर्मा का ग्रामीण प्रवास केवल विशेष अवसरों तक सीमित नहीं बल्कि उनकी कार्यशैली का निरंतर हिस्सा है। इसी क्रम में एक वाक्या का प्रसारण जिले का है, जहां बंबोरी गाँव में भी रात्रि विश्राम एवं ग्राम चौपाल के दौरान ग्रामीणों के बीच पहुँचकर आत्मीय संवाद हुआ। सीकर के जाजोद, अजमेर के कडैल, जालौर के पंसेरी, जयपुर के ठिकरिया, बांसवाड़ा के चुड़ादा, दूंगरपुर के धम्बोला और उदयपुर के बीड़ा समेत कई गाँवों में उन्होंने रात्रि चौपाल किए। जहां जन–आकांक्षाओं के अनुरूप मौके पर ही कई महत्वपूर्ण स्वीकृतियां जारी की गईं।

ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास में ग्राम रथ अभियान भजनलाल सरकार की वह निर्णायक पहल है, जिसने ‘सरकार जनता के द्वार पर’ के संकल्प को हकीकत में बदल दिया। यह अभियान साबित करता है कि डबल इंजन सरकार सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि राजस्थान के दूर दराज के गाँव तक विकास और जागरूकता पहुँचा रही है। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाएं अपनी बात रख सकें, सुरक्षित और सशक्त हो सकें इसको सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री का अनूठा संबल सखी अभियान भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक बेटे, एक भाई, एक पिता की तरह अपने गाँवों में बसे उन सभी परिवारों की चिंता और प्रगति के लिए मुख्यसेवक भजनलाल शर्मा का

यह एक सफल प्रयास है।

इतना ही नहीं भजनलाल सरकार ने वर्षों से जुझ रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जल समझौते पर हस्ताक्षर कर राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के हजारों गाँवों को पेयजल व सिंचाई का स्थायी समाधान मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के हर गाँव और ढाणी के घरों में नल से जल पहुँचाना सुनिश्चित किया। दौसा और सवाई माधोपुर की दशकों पुरानी जल समस्या भी अब इतिहास बनने जा रही है। शेखावाटी अंचल के लिए 34,000 करोड़ रुपये का यमुना जल समझौता हुआ है, जिसके तहत 1,622 करोड़ रुपये से पनौती कृत्रिम जलाशय बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अथक प्रयासों से राजस्थान को इस परियोजना से 124 मिलियन क्यूबिक मीटर जल आवंटित हुआ है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के जल हिस्से का बड़ा भाग राजस्थान और दिल्ली को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया, जिससे शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, चूरू, झुंझुनू) में पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता मजबूत होगी। वहीं नर्मदा समझौते के तहत जालौर, बाड़मेर और बालोतरा के लिए अतिरिक्त पानी जुटाने की डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके अलावा कोटा–बीकानेर–झालावाड़ के लिए 7,355 करोड़ रुपये की ‘परवन’ परियोजना, गंगानहर के आधुनिकीकरण के लिए 1,742 करोड़ रुपये और बांसवाड़ा क्षेत्र में 2,500 करोड़ रुपये की माही कैनाल परियोजना पर काम जारी है। ग्रामीण

युवाओं को स्वरोजगार के लिए हर ग्राम पंचायत में चरणबद्ध अटल ज्ञान केंद्र और खेल मैदान तैयार हो रहे हैं।

त्यौहारों पर किराये की मनमानी : बाजार की आजादी या उपभोक्ता की मजबूरी?

इन्वेंट्री सुरक्षित करते हैं। इसके बाद इन कमरों और सीटों को मांग, उपलब्धता और व्यावसायिक रणनीति के आधार पर अलग–अलग मलतब यह नहीं है कि हर एयरलाइन और होटल को अपनी वास्तविक उपलब्ध इन्वेंट्री का एक पर्याप्त हिस्सा अपने स्वयं के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधे उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रखना होगा। ट्रेवल एजेंसियां और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खत्म करने की जरूरत नहीं है। वे उपभोक्ता को सुविधा, तुलना, पैकेज और दूसरी सेवाएं देते हैं। लेकिन उपभोक्ता के पास कम से कम एक डायरेक्ट ग्राइस बेंचमार्क जरूर होना चाहिए।

इसी के साथ सरकार एक दूसरा महत्वपूर्ण सुधार कर सकती है: रेफरेंस प्राइसिंग सिस्टम। मसलन, किसी टिकट या होटल के कमरे को कीमत को अचानक मनमाने स्तर तक बढ़ाने के बजाय पिछले दो से तीन महीनों के वास्तविक बुकिंग डेटा के आधार पर एक पारदर्शी मूल्य निर्धारण बेंचमार्क बनाया जा सकता है। यहां वॉल्यूम–वेटेड एवरेज ग्राइस एक उपयोगी मॉडल हो सकता है। सरकार को ऐसा प्रावधान बनाने पर विचार करना चाहिए कि पिछले दो से तीन महीनों के वॉल्यूम–वेटेड औसत मूल्य की तुलना में किसी हवाई टिकट या होटल के कमरे का किराया दोगुने से अधिक न हो। यानी सामान्य परिस्थितियों में निर्धारित संदर्भ अवधि के औसत मूल्य को तुलना में अधिकतम दो गुना तक ही किराया लिया जा सके। इससे एयरलाइंस और होटल मांग बढ़ने पर उचित मुनाफा कमा सकेंगे, लेकिन त्यौहारों और छुट्टियों के दौरान किरायों में होने वाली असामान्य बढ़ोतरी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 15 मार्च को टिकट बुक कर रहा है तो सिस्टम पिछले दो महीनों या निर्धारित संदर्भ अवधि में उसी रूत, समान यात्रा श्रेणी और समान परिस्थितियों में वास्तविक रूप से बिके टिकटों के वॉल्यूम–वेटेड औसत

मूल्य को एक संदर्भ बिंदु मान सकता है। यदि 16 मार्च को बुकिंग हो रही है तो संदर्भ विंडो भी स्वतः ही आगे की गणना करेगी। इसका मतलब यह नहीं कि टिकट की कीमत हमेशा उसी औसत पर स्थिर रहे। मांग, समय, सीट उपलब्धता और परिचलन लाभ के आधार पर कीमत में वृद्धि की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन एक निर्धारित सीमा से अधिक असामान्य वृद्धि के लिए पारदर्शी कारण और नियम होने चाहिए। होटलों के लिए भी इसी तरह का मॉडल विकसित किया जा सकता है। समान कमरे की सामान्य दर, पिछले कुछ सप्ताह का वास्तविक बुकिंग मूल्य, सप्ताहांत का प्रभाव, स्थानीय आयोजन, कमरे की उपलब्धता और मांग जैसे कारकों को शामिल करके एक डायनेमिक लेकिन नियंत्रित प्राइसिंग बैड बनाया जा सकता है। यहां मांग और महत्वपूर्ण बात है। सरकार को केवल एयरलाइन और होटल पर ही निगरानी नहीं रखनी चाहिए। डिजिटल ट्रेवल मार्केट प्लेस और बड़े मध्यस्थों की भूमिका भी पारदर्शी होनी चाहिए। उपभोक्ता को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि कीमत में मूल किराया या कमरे का शुल्क कितना है, टैक्स कितना है, प्लेटफॉर्म शुल्क कितना है और अन्य शुल्क कितना है। आज समस्या यह है कि उपभोक्ता अक्सर अंतिम कीमत देखकर चौंकता है, लेकिन उस कीमत के निर्माण की पूरी तस्वीर उसके सामने नहीं होती। सरकार चाहें तो एक राष्ट्रीय Travel Price Transparency Framework बना सकती है, जिसमें एयरलाइंस, होटल और ऑनलाइन ट्रेवल कंपनियों को मानकीकृत तरीके से मूल्य प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जाए। त्यौहारों के दौरान विशेष निगरानी भी की जा सकती है। जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, नए साल, लंबे वीकेंड या बड़े धार्मिक आयोजनों के समय सरकार असामान्य मूल्य वृद्धि की निगरानी करे।

लेकिन यह निगरानी मूल्य नियंत्रण नहीं होनी चाहिए। सरकार को

यह नहीं कहना चाहिए कि एयरलाइन अधिकतम 5,000 ही ले सकती है या होटल 3,000 से ज्यादा नहीं ले सकता, बल्कि यह देखना चाहिए कि कहीं बाजार की स्थिति का फायदा उठाकर कीमतों में असामान्य और अपारदर्शी वृद्धि तो नहीं की जा रही।

आखिर एयरलाइन और होटल भी व्यवसाय हैं। उनके विमानों को उड़ाना है, कर्मचारियों को वेतन देना है, ईंधन और खरखाव का खर्च उठाना है। होटलों को स्टाफ, बिजली, खरखाव और दूसरी लागतें उठानी हैं। इसलिए उन्हें मुनाफा कमाने का पूरा अधिकार है। मुद्रा मुनाफा रोकना नहीं है। मुनाफे की सीमा तय करना भी नहीं है। मुद्रा है बाजार को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष बनाना।

भारत जैसे विशाल देश में त्यौहारों के समय यात्रा कोई विलासिता नहीं रह जाती। करोड़ों लोग अपने परिवारों से मिलने, धार्मिक यात्राओं, सामाजिक कार्यक्रमों और जरूरी कामों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे समय में अगर टिकट और होटल के कमरे अचानक इतने महंगे हो जाएं कि सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार यात्रा ही न कर सके, तो सरकार को कम से कम बाजार की संरचना की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। समाधान प्रतिबंध नहीं, स्मार्ट रेगुलेशन है। एयरलाइन और होटल को कमाने दीजिए। ट्रेवल एजेंसियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी अपना कारोबार करने दीजिए। लेकिन

परिवारों की भी की जा सकती है। जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, नए साल, लंबे वीकेंड या बड़े धार्मिक आयोजनों के समय सरकार असामान्य मूल्य वृद्धि की निगरानी करे।

लेकिन यह निगरानी मूल्य नियंत्रण नहीं होनी चाहिए। सरकार को

रही है। श्रीगंगानगर जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जोधपुर डिस्कॉम के 12 जिलों में सबसे आगे रहा है। सीमावर्ती गाँवों को अब ‘अंतिम’ नहीं, बल्कि ‘प्रथम’ गाँव बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार की वाइब्रेंट विलेजेंज प्रोग्राम– के तहत राजस्थान के 184 रणनीतिक सीमावर्ती गाँवों का समटा विकास किया जा रहा है। विश्वपटल पर राजस्थान की शान यहां की रंगारंग संस्कृति और सभ्यता है जिसको महिला शक्ति ने अपने कठोर तप से समृद्ध किया है। प्रदेश में 4.53 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 52.43 लाख परिवार आजीविका संवर्धन से जुड़े हैं। लखपति दीदी बने चुकी हैं, जो वर्ष 2026–27 के 25 लाख के लक्ष्य का लगभग 74 प्रतिशत है। प्रयास गाँव की महिलाओं को बचत से स्वरोजगार और स्वरोजगार से उध्मिता की ओर ले जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार के सहयोग से केंद्र की ‘भव्या’ पहल के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, बालोतरा, दौसा, खुशखेड़ा–बिवाड़ी–नीमराना और जोधपुर–पाली–मारवार इंडस्ट्रियल एरिया को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, साथ ही दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे का लाभ उठाने के लिए दौसा–बाँदीकुड़ औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विकास की यात्रा का स्पष्ट संदेश है कि विकसित भारत2047 और विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को सिद्ध करने का रास्ता हमारे गाँवों के घर–आँगन और गलियों से होकर गुजरता है।

–पूर्णिमा जैमिनी,

यंग मीडिया सहायक,

डीआईपीआर



सुनील दत्त गोयल

त्यौहार आते ही देश में एक पुरानी समस्या फिर सामने खड़ी हो जाती है। टेन की सीटें मिलना मुश्किल, हवाई टिकट कई गुना महंगे और होटल के कमरे सामान्य दिनों की तुलना में तीन से पाँच गुना तक महंगे। सवाल यह है कि आखिर त्यौहार और छुट्टियों के दौरान ऐसा क्या बदल जाता है कि कुछ दिनों के लिए यात्रा करना आम आदमी की पहुँच से बाहर हो जाता है?

सामान्य तर्क यही दिया जाता है कि यह डिमांड और सप्लाई का खेल है। मांग ज्यादा है तो कीमत ज्यादा होगी। बाजार अर्थव्यवस्था में यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। एयरलाइन और होटल निजी व्यवसाय हैं। उन्हें मुनाफा कमाने का अधिकार है और सरकार को किसी निजी कंपनी की व्यावसायिक व्यवहार्यता खत्म करने चाहिए। लेकिन सवाल वहां सुरू होता है जहां दायनेमिक प्राइसिंग और बाजार की वास्तविक प्रतिस्पर्धा के बीच अंतर खत्म हो जाता है।

बहुत कम लोग इस पूरी व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण परत को समझते हैं। बड़ी ट्रेवल एजेंसियां, टूर ऑपरेटर और ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म कई बार होटल के धर्मिक और एयरलाइन की सीटों की बड़ी संख्या पहले से अंडरराइटिंग या ब्लॉक कर लेते हैं। कुछ मामलों में वे निश्चित संख्या में कमरे या सीटें बेचने की गारंटी भी देते हैं, जबकि अन्य मामलों में कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट के जरिए

यह डिमांड और सप्लाई का खेल है। मांग ज्यादा है तो कीमत ज्यादा होगी। बाजार अर्थव्यवस्था में यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। एयरलाइन और होटल निजी व्यवसाय हैं। उन्हें मुनाफा कमाने का अधिकार है और सरकार को किसी निजी कंपनी की व्यावसायिक व्यवहार्यता खत्म करने चाहिए। लेकिन सवाल वहां सुरू होता है जहां दायनेमिक प्राइसिंग और बाजार की वास्तविक प्रतिस्पर्धा के बीच अंतर खत्म हो जाता है।

बहुत कम लोग इस पूरी व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण परत को समझते हैं। बड़ी ट्रेवल एजेंसियां, टूर ऑपरेटर और ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म कई बार होटल के धर्मिक और एयरलाइन की सीटों की बड़ी संख्या पहले से अंडरराइटिंग या ब्लॉक कर लेते हैं। कुछ मामलों में वे निश्चित संख्या में कमरे या सीटें बेचने की गारंटी भी देते हैं, जबकि अन्य मामलों में कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट के जरिए

यह डिमांड और सप्लाई का खेल है। मांग ज्यादा है तो कीमत ज्यादा होगी। बाजार अर्थव्यवस्था में यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। एयरलाइन और होटल निजी व्यवसाय हैं। उन्हें मुनाफा कमाने का अधिकार है और सरकार को किसी निजी कंपनी की व्यावसायिक व्यवहार्यता खत्म करने चाहिए। लेकिन सवाल वहां सुरू होता है जहां दायनेमिक प्राइसिंग और बाजार की वास्तविक प्रतिस्पर्धा के बीच अंतर खत्म हो जाता है।

लेकिन यह निगरानी मूल्य नियंत्रण नहीं होनी चाहिए। सरकार को

यह नहीं कहना चाहिए कि एयरलाइन अधिकतम 5,000 ही ले सकती है या होटल 3,000 से ज्यादा नहीं ले सकता, बल्कि यह देखना चाहिए कि कहीं बाजार की स्थिति का फायदा उठाकर कीमतों में असामान्य और अपारदर्शी वृद्धि तो नहीं की जा रही।

आखिर एयरलाइन और होटल भी व्यवसाय हैं। उनके विमानों को उड़ाना है, कर्मचारियों को वेतन देना है, ईंधन और खरखाव का खर्च उठाना है। होटलों को स्टाफ, बिजली, खरखाव और दूसरी लागतें उठानी हैं। इसलिए उन्हें मुनाफा कमाने का पूरा अधिकार है। मुद्रा मुनाफा रोकना नहीं है। मुनाफे की सीमा तय करना भी नहीं है। मुद्रा है बाजार को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष बनाना।

भारत जैसे विशाल देश में त्यौहारों के समय यात्रा कोई विलासिता नहीं रह जाती। करोड़ों लोग अपने परिवारों से मिलने, धार्मिक यात्राओं, सामाजिक कार्यक्रमों और जरूरी कामों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे समय में अगर टिकट और होटल के कमरे अचानक इतने महंगे हो जाएं कि सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार यात्रा ही न कर सके, तो सरकार को कम से कम बाजार की संरचना की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। समाधान प्रतिबंध नहीं, स्मार्ट रेगुलेशन है। एयरलाइन और होटल को कमाने दीजिए। ट्रेवल एजेंसियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी अपना कारोबार करने दीजिए। लेकिन

परिवारों की भी की जा सकती है। जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, नए साल, लंबे वीकेंड या बड़े धार्मिक आयोजनों के समय सरकार असामान्य मूल्य वृद्धि की निगरानी करे।

लेकिन यह निगरानी मूल्य नियंत्रण नहीं होनी चाहिए। सरकार को

यह नहीं कहना चाहिए कि एयरलाइन अधिकतम 5,000 ही ले सकती है या होटल 3,000 से ज्यादा नहीं ले सकता, बल्कि यह देखना चाहिए कि कहीं बाजार की स्थिति का फायदा उठाकर कीमतों में असामान्य और अपारदर्शी वृद्धि तो नहीं की जा रही।

आखिर एयरलाइन और होटल भी व्यवसाय हैं। उनके विमानों को उड़ाना है, कर्मचारियों को वेतन देना है, ईंधन और खरखाव का खर्च उठाना है। होटलों को स्टाफ, बिजली, खरखाव और दूसरी लागतें उठानी हैं। इसलिए उन्हें मुनाफा कमाने का पूरा अधिकार है। मुद्रा मुनाफा रोकना नहीं है। मुनाफे की सीमा तय करना भी नहीं है। मुद्रा है बाजार को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष बनाना।

भारत जैसे विशाल देश में त्यौहारों के समय यात्रा कोई विलासिता नहीं रह जाती। करोड़ों लोग अपने परिवारों से मिलने, धार्मिक यात्राओं, सामाजिक कार्यक्रमों और जरूरी कामों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे समय में अगर टिकट और होटल के कमरे अचानक इतने महंगे हो जाएं कि सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार यात्रा ही न कर सके, तो सरकार को कम से कम बाजार की संरचना की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। समाधान प्रतिबंध नहीं, स्मार्ट रेगुलेशन है। एयरलाइन और होटल को कमाने दीजिए। ट्रेवल एजेंसियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी अपना कारोबार करने दीजिए। लेकिन

परिवारों की भी की जा सकती है। जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, नए साल, लंबे वीकेंड या बड़े धार्मिक आयोजनों के समय सरकार असामान्य मूल्य वृद्धि की निगरानी करे।

लेकिन यह निगरानी मूल्य नियंत्रण नहीं होनी चाहिए। सरकार को

यह नहीं कहना चाहिए कि एयरलाइन अधिकतम 5,000 ही ले सकती है या होटल 3,000 से ज्यादा नहीं ले सकता, बल्कि यह देखना चाहिए कि कहीं बाजार की स्थिति का फायदा उठाकर कीमतों में असामान्य और अपारदर्शी वृद्धि तो नहीं की जा रही।

आखिर एयरलाइन और होटल भी व्यवसाय हैं। उनके विमानों को उड़ाना है, कर्मचारियों को वेतन देना है, ईंधन और खरखाव का खर्च उठाना है। होटलों को स्टाफ, बिजली, खरखाव और दूसरी लागतें उठानी हैं। इसलिए उन्हें मुनाफा कमाने का पूरा अधिकार है। मुद्रा मुनाफा रोकना नहीं है। मुनाफे की सीमा तय करना भी नहीं है। मुद्रा है बाजार को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष बनाना।

भारत जैसे विशाल देश में त्यौहारों के समय यात्रा कोई विलासिता नहीं रह जाती। करोड़ों लोग अपने परिवारों से मिलने, धार्मिक यात्राओं, सामाजिक कार्यक्रमों और जरूरी कामों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे समय में अगर टिकट और होटल के कमरे अचानक इतने महंगे हो जाएं कि सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार यात्रा ही न कर सके, तो सरकार को कम से कम बाजार की संरचना की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। समाधान प्रतिबंध नहीं, स्मार्ट रेगुलेशन है। एयरलाइन और होटल को कमाने दीजिए। ट्रेवल एजेंसियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी अपना कारोबार करने दीजिए। लेकिन

परिवारों की भी की जा सकती है। जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, नए साल, लंबे वीकेंड या बड़े धार्मिक आयोजनों के समय सरकार असामान्य मूल्य वृद्धि की निगरानी करे।

लेकिन यह निगरानी मूल्य नियंत्रण नहीं होनी चाहिए। सरकार को



पंडित अनिल शर्मा

तुला, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह आज राजयोग सूर्योदय से दिन 2:52 तक है। सर्वाथ सिद्धि योग और रविपुष्य योग सूर्योदय से रात्रि 4